SHRI A.G. KULKARNI: Sir, you are criticising but this is affection for their father.

MR. CHAIRMAN: That is what I said. The father should show his affection and sagacity outside the House. Let the proceedings go on.

SHRI VIREN J. SHAH: Sir, this question has already taken 25 minutes. ..*(Interruptions)*...

SHRI A.G. KULKARNI: The tradition in younger ladies is just to create disturbance for father also, the decentralised powerloom and the handloom sector must receive the concessions through their exports, through merchant exporters and not through the registered export houses. May I know the Minister's reaction to it?

श्री अशोक गहलोत: चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने जो मैनुफैक्चरर इन्टाइटिलमेंट कोटा की बात की है उसमें मैं इनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि पावरलूम में अभी हमने फर्स्ट टाइम तीन परसेंट कोटा इंट्रोड्यूस किया है और हमारी खुद की कोशिश है कि जो पावरलूम और हैंडलूम में काम करने वाले लोग है, कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे कि, सीधे उनको एक्सपोर्ट का लाभ मिल सके। पर जब तक वे खुद एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कोटा इंट्रोड्यूस इसलिये किया है पावरलूम का और हैंडलूम का भी कि कोई तरीका ऐसा बन सके जिससे उनका पूरा लाभ सीधे मिल सके।

MR. CHAIRMAN: Q.No. 262.

मूल्य निर्धारण पद्धति के कारण निर्यात में कमी

*262. **श्री रजनी रंजन साहू:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि सरकार की मूल्य निर्धारण पद्धति के कारण वर्ष 1990-91 के दौरान वस्त्रों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है; और

(ग) क्या सरकार वस्त्रों के निर्यात के मामले में मूल्य निर्धारण पद्धति को समाप्त करने का विचार रखती है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रजनी रंजन साहू: सभापति महोदय, मैंने अपना प्रश्न हिंदी में पूछा था जिसका ट्रांसलेशन शायद गलत कर दिया गया है। मैंने कपड़े से बने वस्त्रों गारमेंट्स के संबंध में पूछा था न कि टेक्सटाइल के संबंध में पूछा था। मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग...

श्री सभापति: जो आपका प्रश्न है वह हिंदी में भी मैंने पढ़ा - "क्या यह सच है कि सरकार की मूल्य निर्धारण पद्धति के कारण वर्ष 1990-91 के दौरान वस्त्रों के निर्यात में कमी आई है।"

श्री रजनी रंजन साहू: वस्त्र, गारमेंट...

श्री सभापति: वस्त्र इज वस्त्र। गारमेंट भी वस्त्र है और जो गारमेंट नहीं है वह भी वस्त्र है।

श्री रजनी रंजन साहू: मेरा प्रश्न गारमेंट से था।

श्री सभापति: आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। हिंदी में भी बिल्कुल उन्होंने शुद्ध दिया है।

श्री रजनी रंजन साहू: मेरा तात्पर्य गारमेंट से था। सिले हुए वस्त्रों से था। सिले हुए वस्त्रों के संबंध में था।

एक माननीय सदस्य: जिन्होंने आपको प्रश्न दिया वह ठीक नहीं लिखा।

श्री रजनी रंजन साहू: मैंने अपना ही बनाया था ...*(व्यवधान)* आप जरा चुप रहिए।

मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को खुले बाजार में प्रतियोगिता की ओर ले जा रहे हैं, प्रतियोगिता से उपभोक्ता को सही सही कीमत पर सामान मिलता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिले हुए वस्त्र जिन्हें कि गारमेंट्स कहते हैं, उसके एक्सपोर्ट में सरकार द्वारा कोई फ्लोर प्राइस तय की जाती है या इसमें सरकार का हाथ होता है कि इतनी ही कीमत पर बेची जाये? इससे ज्यादा कीमत पर या कम कीमत पर नहीं बेचा जाये? मेरा मतलब है कि फ्लोर प्राइस तय करने की जो पद्धति है आज, उसे हटाने के लिए कोई व्यवस्था या प्रावधान मंत्री महोदय सोच रहे हैं?

श्री अशोक गहलोत: माननीय चैयरमेन साहब, फ्लोर प्राइस फिक्सिंग उन्हीं आयटम्स में की जाती है जोकि कोटा आयटम्स हैं और कोटा आयटम्स में मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इसलिए करते हैं क्योंकि क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, एम॰एफ॰ए॰ के अंतर्गत, इसलिए हम चाहेंगे कि जितनी क्वांटिटी मिली है उसका उपयोग इस प्रकार से किया जाये जिससे कि हम ज्यादा-से-ज्यादा फोरेन एक्सचेंज कमा सकें। इसलिए मिनीमम एक्सपोर्ट प्राइस को फिक्स करके ही हम चल सकते हैं। इसको हटाने का कोई इरादा नहीं है।

श्री रजनी रंजन साहू: सभापति महोदय, इस फ्लोर प्राइस को रखने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ होता है और आज के जमाने में जब कि हमारा कंपटीशन इंडोनेशिया, श्रीलंका और पाकिस्तान से सिले हुए वस्त्र

का हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यह हमारे एक्सपोर्ट के लिए बाधक बन सकता है और जैसाकि मंत्री महोदय ने अभी कहा कि यह एक कीमत रखते हैं इसलिए कि एक्सपोर्ट की वेल्यू बढ़े, एक्सपोर्ट की आय बढ़े तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो नया एग्रीमेंट "गैट" का होनेवाला है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर ये फ्लोर प्राइस आज हटा दी जाये तो उसका क्या असर उस पर पड़ेगा?

श्री अशोक गहलोत: चैयरमेन साहब, कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टे उससे फायदा होगा। जैसाकि मैंने आपको निवेदन किया फ्लोर प्राइस इसलिए फिक्स की जाती है कि मैक्सीमम फारेन एक्सचेंज हम ले सकें। दूसरे इसमें हमारे खुद के जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फायदा रहता है क्योंकि फारेन बायर्स उनसे बार्गेनिंग करते हैं अगर हम फ्लोर प्राइस नहीं रखते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि इससे हमें कोई नुकसान होनेवाला है। तीसरे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे अनहैल्दी कपटीशन नहीं होता है। इसलिए माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जिसे हम फ्लोर प्राइस भी कहते हैं, उसको रखना बहुत जरूरी है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड आयटम्स हमारे पास में हैं।

SHRI M.S. GURUPADASWAMY: Sir, quite a large number of government exporters are coming to the field. I am told that a lot of restrictions are being imposed on these manufacturers. They cannot get adequate foreign exchange to import necessary machineries for that purpose. That has hindered them. Secondly, this price system has been fixed sometime back. A lot of things have happened in between. I would like to know from the Minister whether there is any proposal to revise the floor price on Government exports.

श्री अशोक गहलोत: चैयरमेन साहब, मशीनरी एक्सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी पर कंसेसन भी मिला हुआ है, इसलिए ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है और समय-समय पर जो शिकायत आती हैं, उसमें जो डेलीगेशन मिलते हैं, जो ज्ञापन हमारे पास आते हैं, उनके माध्यम से हम लोग उन समस्याओं को हल कर लेते हैं। इसलिए माननीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत देंगे तो उस समस्या को हम दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे।

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir my information is that after devaluation of 2nd July, the importers are asking for reduction in the price of textiles. I would like to know from the hon. Minister as to what was the amount of export in dollar terms between April 1990 and January 1991 and what was the value in dollar terms of the exports made for the year 1991-92 which you have given in rupee terms--Rs.9169 crores? How do you compare it? The thrust is to earn more foreign exchange. Have your exports increased by 22 per cent after devaluation to see that we also get the same amount of foreign exchange which we were getting earlier. Will the Minister let us know whether in real terms the export in textiles has gone down?

श्री अशोक गहलोत: सर, इस सवाल से उनके क्वेश्चन का संबंध तो नहीं है।

श्री सभापति: नहीं, है। वह पूछ रहे हैं कि जो आपने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, उसमें डालर टर्म्स में क्या हुआ है? That is all. A very simple question.

श्री अशोक गहलोत: माननीय, सभापति जी, डालर टर्म में भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। अप्रैल 1990-91 में 3,683.09 मिलियन डालर का जो एक्सपोर्ट हुआ, वह फिर 1991-92 में 3,770.15 मिलियन डालर टर्म में है। इस तरह से इन्क्रीज़ 2.4 प्रतिशत है।

श्री सभापति: डालर में भी बढ़ा है। That is good.

श्री अशोक गहलोत: जी, हां। जो टार्गेट हमने बनाया था, उसके हिसाब से 4,616.38 मिलियन डालर था। उसके हिसाब से 81.7 प्रतिशत टार्गेट अचीव हुआ है।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, the question is ...

MR. CHAIRMAN: He asked, "What about dollars?" He has given in dollars. In dollars it has increased ....*(Interruptions)*... He has answered those questions. I can't remember them.

श्री मोहम्मद सलीम: डीवैल्युएशन के बाद, सवाल पूछा गया था ...**(व्यवधान)** उसका जवाब नहीं मिला।

SHRI JAGESH DESAI: Sir, I have asked whether the exports in 1991-92 have gone down as compared to the figures of 1990-91. That is what I wanted to know. Sir, I am told that they have gone down.

श्री अशोक गहलोत: वही मैंने बताया है, सर।

MR. CHAIRMAN: His information must be authentic.

श्री अशोक गहलोत: मैं डालर टर्म्स में ही बात कर रहा हूं। डालर टर्म्स के अंदर भी हमारा एक्सपोर्ट 2.4 प्रतिशत बढ़ा है। जो पीरियड माननीय सदस्य बता रहे हैं, अप्रैल 1990 + जनवरी 1991, इससे कम्पेयर किया है, अप्रैल 1991-92 — इसमें 3,683.09 मिलियन डालर

का एक्सपोर्ट हुआ, अप्रैल 1990 से जनवरी, 1991 में 3,770.15 मिलियन डालर का एक्सपोर्ट हुआ। इस प्रकार 2.4 प्रतिशत बढ़ा है और जैसा मैंने कहा कि जो टार्गेट हमने बनाया था, उसके मुताबिक 81.75 प्रतिशत हमने अचीव कर लिया है। हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक इसे पूरा अचीव कर लेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने बताया कि उनकी हार्दिक इच्छा है कि एम०एफ०ए० हट जाए और वह जी०ए०टी०टी० के अन्तर्गत आ जायें। आप जानते हैं कि जी०ए०टी०टी० के अन्तर्गत आने की पूर्व शर्त है डनकल प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करना। बिना डनकल प्रस्तावों पर साईन किये हम जी०ए०टी०टी० के मेम्बर नहीं रह सकते।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि डनकल प्रस्तावों में टेक्सटाईल कोटा पर दस साल की समय सीमा लगाने का प्रावधान है। तो जिस तरह से आपने कहा कि प्राईस फिक्सेशन सिस्टम तो हमारे लिये फायदेमंद होगा, तो यह टैक्सटाईल कोटा पर दस साल की पाबंदी भी क्या हमारे लिए फायदेमंद होगी, या इससे देश को नुकसान होगा? आपके मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अशोक गहलोत: यह प्रश्न तो पहले वाले क्वश्चन से संबंधित है, पर मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। माननीय सदस्या ने जो कहा है एम०एफ०ए० को हम फेवर नहीं करते हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारी कोशिश थी, अगस्त 1981 में जब यह समाप्त हो रहा था, तो इसका टर्म आगे नहीं बढ़े हमने भी कहा और पाकिस्तान ने भी कहा, पर दूसरे कंट्रीज़ ने हमारा साथ नहीं दिया और इम्पोर्टिंग कंटीज़ के इंट्रेस्ट में यह नहीं था कि वह खत्म हो। कोई भी डनकल प्रस्ताव आए, उसको हम नहीं चाहेंगे कि डनकल प्रस्ताव में यह एम०एफ०ए० और बढ़े, पर क्योंकि डनकल प्रस्ताव है, उसमें मैंने कहा कि उस पर चर्चा होनी है और इसलिए जब चर्चा होगी, तो हम लोग विचार करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: नहीं, आपके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अशोक गहलोत: हमारे मंत्रालय की प्रतिक्रिया है कि इसमें जो प्रस्ताव किया गया है, उससे हमको लाभ नहीं होगा।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय सभापति जी, मंत्री महोदय ने जो तीनों प्वाइंट्स का उत्तर दिया है, वह सब नेगेटिव है।

श्री सभापति: आप प्रश्न कर लीजिए।

SHRI A.G. KULKARNI: Sir, this is due to television. The delay is due to television. Television is delaying the whole thing.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैं जानना चाहता हूं कि बनारसी वस्तु से पांच सौ करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेंज सरकार को मिलता है और जो विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, उसमें बनारसी वस्त्र उद्योग में जो सरकारी खरीद होती है....**(व्यवधान)**

श्री सभापति: आप बनारसी पर आपत्ति नहीं करिए। वह अच्छा है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: जो बनारसी वस्तु की खरीद होती है, वह कोआपरेटिव के माध्यम से करते हैं, लेकिन उस कोआपरेटिव में भी ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो सीधे मैनुफैक्चरर्स से उत्पादन न लेकर के स्वयं एक सही ढंग से सप्लाई नहीं होती।

श्री सभापति: सवाल तो प्राईस है।....**(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय: हम पांच सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देते हैं और उसी संदर्भ में हम प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे जो कोआपरेटिव्स के माध्यम से आप बनारसी वस्त्र लेते हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार है, उसके कारण उद्योग का सही ढंग का मूल्य नहीं मिल पाता और बीच के लोग खा जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ताकि विदेशी मुद्रा कमाकर के जो बुनकर देता है आपको, उसको सीधा उसका लाभ मिल सके।

श्री अशोक गहलोत: चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक कम्पलेंट बताएंगे तो हम उसकी जांच करवा लेंगे।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Due to unrealistic price fixation by the Government, all efforts pursued by the people in the textile export sector of the North-Eastern region have been completely dampened. It is known that North-Eastern region is very rich in handlooms. Recently due to its particular design North-Eastern region handlooms tend to become popular and are catching foreign market. Considering these factors, I would like to know whether the Government is going to relax the present price structure fixed by the Government for exports.

श्री अशोक गहलोत: माननीय चेयरमैन साहब, इसमें मैंने कहा कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हम फिक्स करते हैं और उसमे एक बेस ईयर लेते हैं और पिछले साल में कितना कोटा, वह फास्ट आइटम था या स्लो, उसके आधार पर हम फिक्स करते हैं। इसलिए इससे अलग करने की तो कोई हमारे पास योजना नहीं है।